

उत्तर प्रदेश शासन

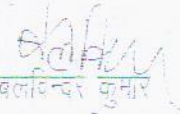
महिला एवं बाल विकास अनुभाग

संख्या- 4931/60-1-10-1/1371/06

लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010

: कार्यालय ज्ञाप : :

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम- 2000 (2006 का संशोधन अधिनियम-33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सजावट संरक्षणात्मक परिवेश, पालन पोषण करण, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुर्व्यवहार से बचन और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समन्वित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहमति पत्र (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) दिनांक 24-11-2010 को हस्ताक्षरित हो जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय की सहमति अनुमति से प्रदेश में दिनांक 24-11-2010 से समन्वित बाल संरक्षण योजना (ICPS) तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गया है। अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी / प्राधिकारी समन्वित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के सम्बन्ध में जारी किए गए भारत सरकार के विज्ञान-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


बलदेव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या- 4931(1)/60-1-10-1/1371/06, तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, CGO, लखनऊ को इस अनुसंध के साथ प्रेषित कि वे इस कार्यालय ज्ञाप को तत्कालीन गजट के अगत अंक में विधायी परिशिष्ट खण्ड-ख एवं भाग-4 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, ना0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5. सनसत प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सनसत विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. सनसत नगडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. सनसत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सनसत अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल अल्पम समिति, जिला स्तर बाई उत्तर प्रदेश।
10. सनसत उपमुख्य परिषदाजा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सनसत जिला परिषदाजा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल हेतु।


बलदेव कुमार
प्रमुख सचिव